

# कोविड ..19 का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का आर्थिक एवं भौगोलिक अध्ययन

**Pappu Lal Kumawat**

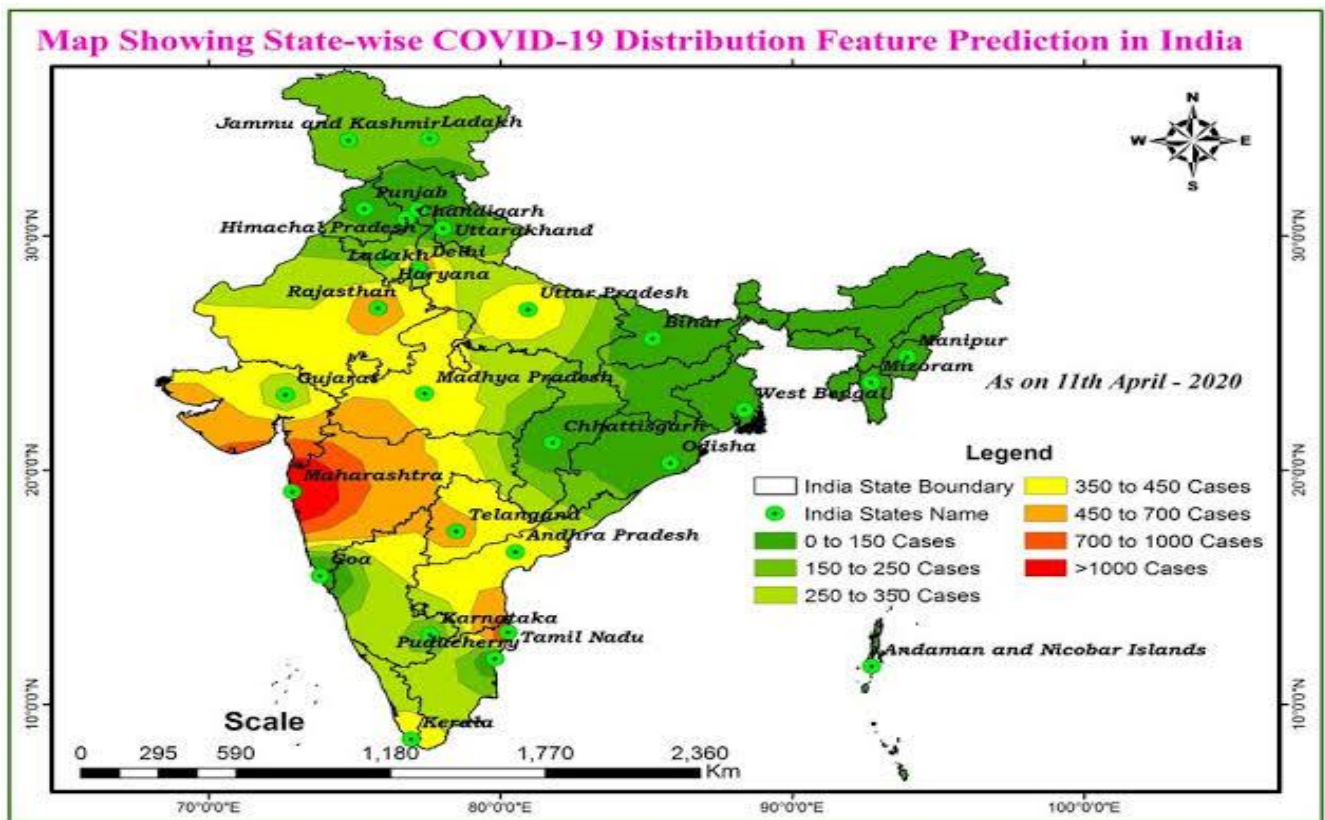
Assistant Professor Geography  
Govt. Girls College Bassi, Chittorgarh.

सार—

शोध समस्या का चयन हम इस तथ्य को नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं कि चीन और दुनिया के अन्य देशों में कोविड-19 के प्रकोप से वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी, व्यापार की आयात-निर्यात नीति, वस्तुओं और उत्पादन में कमी से अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। आयात में चीन पर भारत की निर्भरता बहुत बड़ी है 20 उत्पादों में से जो भारत दुनिया से आयात करता है, उसमें चीन एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है भारत का कुल इलेक्ट्रॉनिक आयात यानी लगभग 45 प्रतिशत चीन पर निर्भर लगभग एक तिहाई मशीनरी और लगभग कार्बनिक रसायन जिन्हे भारत खरीदता है चीन से आते हैं मोटर वाहन और उर्वरकों के लिए भारत के आयात में चीन की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से अधिक है। लगभग 65 से 70 प्रतिशत सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री और लगभग 90 प्रतिशत मोबाईल फोन चीन से आते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण, चीन पर आयात निर्भरता का भारतीय उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है परन्तु अब चीन में हालात सुधर रहे हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ बदलाव देखने को मिले निर्यात मामले में चीन भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात साझेदार है और लगभग 5 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है इसका असर निम्नलिखित क्षेत्रों में भी हो सकता है जैसे कि जैविक रसायन, प्लास्टिक मछली उत्पाद, कपास इत्यादि। हम यह भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि अधिकांश भारतीय कंपनियां चीन के पूर्वी भाग में स्थित हैं चीन में भारत की लगभग 72 प्रतिशत कंपनियां शंघाई, बीजिंग, ग्वांगदोंग, जियांग्स और शानदोंग जैसे प्रांतों में स्थित हैं विभिन्न क्षेत्रों में ये कंपनियां औद्योगिक निर्माण विनिर्माण सेवाओं आईटी और बीपीओ, लॉजिस्टिक्स, रसायन, एयरलाइंस और पर्यटन सहित काम करती हैं अब वहां पर कोविड-19 को लेकर हालात सुधर रहे हैं और चीन फिर से ट्रेक पर आ रहा है कुछ विशेषज्ञों अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं के अनुसार ये कुछ प्रभाव हो सकते हैं:—

**प्रस्तावना**

भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर नजर डाले तो पता लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सातवें स्थान पर है, जनसंख्या में इसका दूसरा स्थान है और केवल 2.4 प्रतिशत क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व की जनसंख्या के 17 प्रतिशत भाग को शरण प्रदान करता है। 1991 से भारत में बहुत तेज आर्थिक प्रगति हुई है जबसे उदारीकरण और आर्थिक सुधार की नीति लागू की गयी है और भारत विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरकर आया है सुधारों से पूर्व मुख्य रूप में भारतीय उद्योगों और व्यापार पर सहकारी नियंत्रण का बोलबाला था और सुधार लागू करने से पूर्व इसका जोरदार विरोध भी हुआ परन्तु आर्थिक सुधारों के अच्छे परिणाम सामने आने से विरोध काफी हद तक कम हुआ है। और एक बड़ा हिस्सा इन सुधारों से अभी भी लाभान्वित नहीं हुये हैं।



लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधि का नुकसान:-

- लोगों को नौकरी खोने के कारण आय का नुकसान
- वैश्विक बंद के कारण निर्यात में गिरावट
- कई क्षेत्रों में उत्पादन में व्यवधान

नवीनतम अर्थव्यवस्था के पूर्वानुमान के अनुसार, मंदी की स्थिति में आने वाले देशों और दिवालिया होने वाली कंपनियों में प्रवेश करने की संभावना बढ़ गई है। अरुण सिंह, मुख्य अर्थशास्त्री डन और ब्रैडस्ट्री इंडिया ने कहा चीन के अलावा अन्य वैश्विक विनिर्माण केन्द्रों में भी तालेबंदी की जा रही है जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक विकास में कमजोरी बढ़ सकती है।

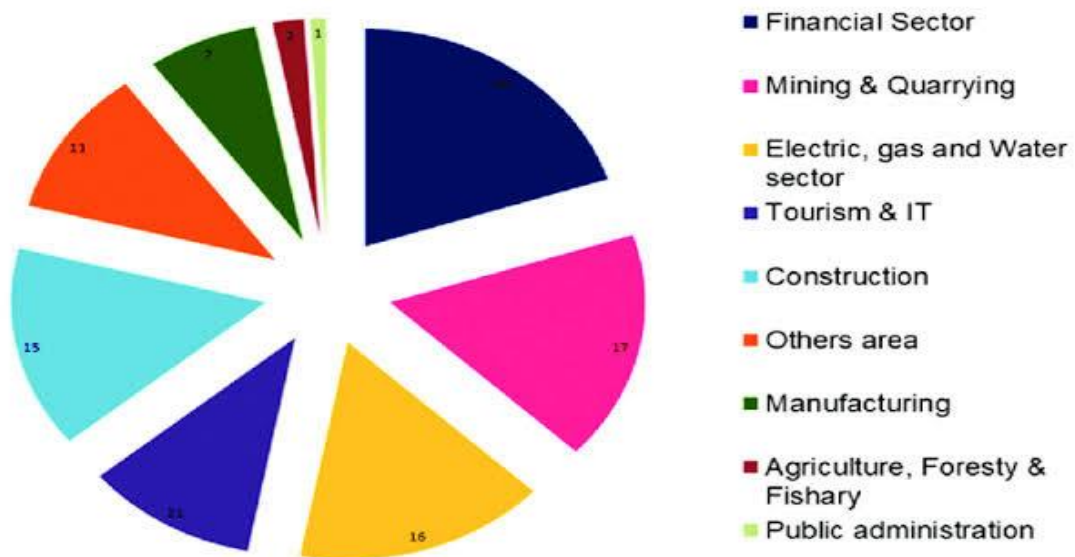
भारत की आर्थिक वृद्धि पर सिंह ने कहा भारत के 21 दिनों के लॉकडाउन को देखते हुए भारत की जीडी.पी. वृद्धि हमारे फाईनेनशियल ईयर 20 के लिए 5 प्रतिशत के पहले के अनुमान से आगे मध्यम रहने की उम्मीद है। वाणिज्यिक गतिविधियों पर तालाबन्दी और प्रतिबन्ध से वैश्विक कीमत में तेज गिरावट और अन्य प्रमुख वस्तुओं जैसे ऊर्जा, धातुओं और उर्वरकों में कीमत घट जाएगी और मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ने की उम्मीद है।

### कोविड-19 का विश्लेषणात्मक अध्ययन

- कोरोना वायरस के कारण भारत में पैदा हुई आर्थिक चुनौतियां अर्थव्यवस्था पर इन स्थितियों का कितना गहरा असर पड़ेगा ये दो बातों पर निर्भर करेगा एक तो ये कि आने वाले वक्त में कोरोना वायरस की समस्या भारत में कितनी गंभीर होती है और दूसरा कि कब तक इस पर काबू पाया जाता है। कोरोना वायरस ने न केवल भारत की बल्कि अर्थव्यवस्था की हालत खराब कर रखी है विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के कारण भारत की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ने वाला है कोरोना से भारत की आर्थिक वृद्धि दर में भारी गिरावट आएगी। वर्ल्ड बैंक के अनुमान के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर मात्र 5 प्रतिशत रह जाएगी तो वही 2020-21 में तुलनात्मक आधार पर अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में भारी गिरावट आएगी जो घटकर मात्र 2.8 प्रतिशत रह जाएगी रिपोर्ट में कहा गया है कि यह महामारी ऐसे समय में आई है जबकि वित्तीय क्षेत्र पर दबाव के कारण पहले से ही भारतीय इकोनॉमी सुस्ती की मार झेल रही थी कोरोना वायरस के कारण इस पर और दबाव बढ़ा है। जिस बात का डर था वही होने जा रहा है। कोरोना पर नियंत्रण के उद्देश्य से 25 मार्च 2020 को देश में लॉकडाउन शुरू हुआ तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 500 थी। बीस दिनों में यह संख्या बढ़कर दस हजार तक पहुँच गई। और अब हालात ये है कि देश में एक दिन के भीतर 40 हजार मरीज सामने आ गए। विशेषज्ञों का मानना है कि देश में महामारी के सामुदायिक, संक्रमण की शुरुआत होने की

आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो इसके कारणों पर भी जाना होगा और इसके समाधान पर भी। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं कि 500 मरीज सामने आने पर केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की तो उसकी मंशा बीमारी के सामुदायिक संक्रमण को रोकने की थी। शुरुआती दौर में राज्य सरकारें भी सतर्क रही और जनता भी देश में 68 दिन लॉकडाउन चला तो हालात नियंत्रण में नजर आए किन्तु जैसे ही लॉकडाउन खुला सरकारें भी बेफ़िक हो गईं व जनता भी। मध्य प्रदेश में चला राजनीतिक नाटक सबके सामने है। राजस्थान में इन दिनों जो हो रहा है किसी से छिपा नहीं है। बीते 10 दिनों से राज्य सरकार होटल में बंद है। मरीजों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है पर सरकार व तमाम राजनीतिक दल जनता की चिंता छोड़कर राजनीतिक राजनीति खेल रहे हैं। ऐसे में कोरोना को बेकाबू होने से भला कौन रोक सकता है। बीते 15 दिनों के हालात का विश्लेषण करें तो लगता नहीं कि राज्य सरकारें कोरोना को लेकर गंभीर रही हैं। ऐसा लगता है जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। उत्तर प्रदेश बिहार और पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन फिर शुरू किया गया है लेकिन गंभीरता कही भी नजर नहीं आ रही। न प्रशासन की सख्ती है और न सतर्कता। देश आज जबरदस्त संकट के दौर से गुजर रहा है इसे गंभीरता के साथ ही लेने की जरूरत है। सवाल यह उठता है कि राजनीतिक टकराव को क्या इस समय टाला नहीं जाना चाहिए? राजनीतिक दलों को क्या मिलकर इस कोरोना महामारी से लड़ना नहीं चाहिए? हालात अभी बिगड़े जरूर हैं लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सामूहिक प्रयास किये जाएं तो बड़े खतरे को टाला जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को लेकर गई तरह की आशंकाएँ जता चुकी हैं। लेकिन हम उसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यही हाल रहा तो कोई आश्चर्य नहीं कि कोरोना मरीजों के मामले में हम अमरीका को भी पीछे छोड़ दें। जरा सोचिए उस स्थिति में देश का क्या होगा। अर्थव्यवस्था पहले ही चौपट हो चुकी है। मरीजों की तादाद इसी तरह बढ़ती रही तो स्थिति नियंत्रण के बाहर होते देर नहीं लगेगी अब भी समय है जब हम खतरों को पहचानें और नए सिरे से कोरोना विरुद्ध रणनीति बनाएँ और सावधानी पूर्वक इसे किस तरह लागू किया जाए कि संक्रमण चक्र भी टूटे और आर्थिक बर्बादी भी कम हो। दर असल कोरोना वायरस के कारण देशभर में लॉकडाउन है सभी फ़ैक्ट्री आफिस,माल्स व्यवसाय आदि सब बंद रहे हैं। घरेलू आपूर्ति और माँग प्रभावित होने के चले आर्थिक वृद्धि दर प्रभावित हुई है वही जोखिम बढ़ने से घरेलू निवेश में सुधार में भी देरी होने की संभावना दिख रही है ऐसे में अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर में पहुँच सकती है। रिपोर्ट में सरकार को वित्तीय और मौद्रिक नीति के समर्थन की जरूरत पर जोर देने की सलाह दी गई चुनौती से निपटने के लिए भारत को इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए जल्द से जल्द ज्यादा प्रभावी कदम उठाना होगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर अस्थायी रोजगार सृजन कार्यक्रमों पर भी ध्यान देना होगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन ने कहा था कि कोरोना वायरस सिर्फ एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट नहीं रहा बल्कि ये एक बड़ा लेबर मार्केट और आर्थिक संकट भी बन गया है जो लोगों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा।

### Sector wise impact of COVID 19



वैश्विक जी.डी.पी. में रोज कमी दर्ज की जा रही है लाखों लोग अपना रोजगार खो चुके हैं। आईएलओ के अनुसार कोरोना वायरस की वजह से देश ढाई करोड़ नौकरियां खतरे में हैं कोविड-19 के कारण चीन से होने वाले आयात

के प्रभावित होने से स्थानीय और बाहरी आपूर्ति में चिताएँ बढ़ी है। सरकार द्वारा कावेडि-19 के प्रसार को रोकने के लिये लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे प्रयासों से औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी बढ़ी है जिससे सार्वजनिक खर्च में भारी कटौती हुई है। लॉकडाउन के कारण कच्चेमाल की उपलब्धता उत्पादन और तैयार उत्पादों के वितरण की श्रृंखला प्रभावित हुई है। जिसे पुनः प्रारम्भ करने में कुछ समय लग सकता है। उदाहरण के लिये उत्पादन स्थगित होने के कारण मजदूरों का पलायन बढ़ा है ऐसे में कंपनियों के लिये पुनः कुशल मजदूरों की नियुक्ति कर पाना एवं पूरी क्षमता के साथ उत्पादन शुरू करना एक बड़ी चुनौती होगी। जिसका प्रभाव अर्थव्यवस्था की धीमी प्रगति के रूप में देखा जा सकता है। खनन और उत्पादन जैसे अन्य प्राथमिक या द्वितीयक क्षेत्रों में गिरावट का प्रभाव सेवा क्षेत्र कंपनियों पर भी पड़ा है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैंसटिमेर ने कहा कि भारत का परिदृश्य अच्छा नहीं है टिमेर ने कहा कि यदि भारत में लॉकडाउन अधिक समय तक जारी रहता है तो यहाँ आर्थिक परिणाम विश्व बैंक के अनुमान से अधिक बुरे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिये भारत को सबसे पहले इस महामारी को फैलने से रोकना होगा और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी को भोजन मिल सकें। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर अनौपचारिक क्षेत्र पर पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था का 50 प्रतिशत जी.डी.पी.अनौपचारिक क्षेत्र से ही आता है। कोरोनाकाल में ज्यादातर कंपनियों की आमदनी में गिरावट दर्ज हुई है हालांकि कुछ कंपनियाँ ऐसी भी हैं जिन्होंने इस दौर में भी जमकर मुनाफा कमाया है देश को उन 20 कंपनियों की सूची तैयार की है जिन्होंने 25 मार्च से 30 जून के बीच अपने मार्केट कैपिटल में 10 हजार करोड़ या इससे अधिक का इजाफा किया है। इस सूची में उम्मीद के अनुरूप फार्मास्युटिकल कंपनियाँ तो हैं ही लेकिन इसके अतिरिक्त ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, मेटल, माइनिंग, टेलीकॉम और डायर्य बिजनेस वाली कंपनियाँ भी शामिल हैं। भारत को चाहिए कि अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भारत में भी प्रतिभाशाली अर्थशास्त्रियों की एक कमेटी का गठन किया जाए।

आइए जानते हैं कि ये 20 कंपनियाँ कौन सी हैं जिन्होंने इस संकट के दौर में अच्छे फंडामेंटल और बेहतर निर्णयों ने दी इन कंपनियों को बढ़त :-

- **रिलायंस इंडस्ट्रीज**— 3,94,374 करोड़ जोड़े अपने मार्केट कैप में इस कंपनी की खास बात यह है कि कंपनी ने अपने जियो प्लेटफॉर्म की हिस्सेदारी बेचकर तीन महाने में 1.8 लाख करोड़ रूपए जूटाए है 12 लाख करोड़ से अधिक मार्केट कैप वाला देश की पहली कंपनी है।
- **सनफार्मा**— 30,960 करोड़ करोड़ रूपए अपने मार्केट कैप में जोड़े इस कंपनी की खास बात यह है कि फार्मास्युटिकल फॉर्मूलेशन में कंपनी दुनिया की दिग्गज कंपनियों को बराबर की टक्कर देती है। वित्त वर्ष 2019-2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट अनुमान से 35 प्रतिशत ज्यादा रहा।
- **महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा**—28,960 करोड़ रूपए अपने मार्केट कैप में जोड़े इस कंपनी की खास बात यह है कि इस साल के जून महीने से कंपनी ने पिछले साल के जून महीने से ज्यादा ट्रेक्टर बेच डाले।
- **ब्रिटानिया**— 27,722 करोड़ रूपए मार्केट कैप इस कंपनी की खास बात यह है कि यह कंपनी देश की सबसे बड़ी बिस्किट निर्माता पारले का साल दर साल मार्केट शेयर छीन रही है।
- **बंधन बैंक**— 26,505 करोड़ अपने मार्केट कैप में जोड़े इस कंपनी की खास बात यह है कि पिछले तीन महीने में 106 फीसदी का रिटर्न। मार्केट कैप 106 फीसदी बढ़ा।
- **अरबिंदो फार्मा**— 25,664 करोड़ रूपए जोड़े मार्केट कैप में इस कंपनी की खास बात यह है कि इस कंपनी के शेयरों ने दो महीने में 13.1 प्रतिशत का रिटर्न दिया है एपीआई की बड़ी उत्पादक।
- **बजाज ऑटो**— 25,503 करोड़ रूपए जोड़े मार्केट कैप में। इस कंपनी की खास बात यह है कि यह देश की दूसरी सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता है वित्त वर्ष 2019-20 में इसका राजस्व 31443.22 करोड़ रूपए और मुनाफा 4,890.40 करोड़ रूपए रहा।
- **मारुती सुजुकी** — 24,314 करोड़ रूपए जोड़े मार्केट कैप में। इस कंपनी की खास बात यह है कि मारुती कंपनी भारतीयों की नब्ज समझती है देश में बिकने वाली दो में से एक कार मारुती की होती है। 2019-20 में पैसेजन व्हीकल सेगमेंट में 51.03 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ शीर्ष स्थान पर बनी रही।
- **सिप्ला**— 21,233 करोड़ रूपए जो मार्केट कैप में इस कंपनी की बात यह है कि सिप्ला कंपनी की बनी दवाईयों की बदौलत ही अफ्रीका एड्स जैसी बीमारी से जीत पाया है। यह देश की प्रमुख फार्मा और बायोटेक्नालॉजी कंपनी है।
- **अदाणी मोटर्स**— 1789 करोड़ रूपए जोड़े मार्केट कैप में। इस कंपनी की खास बात यह है कि उद्योगपति गौतम अदाणी की ये कंपनी देश के छः राज्यों में 10 पोर्ट ऑपरेट कर रही है। 2019-20 में रेवेन्यू 13,734.42 करोड़ रूपए और मुनाफा 3,78,892 करोड़ रूपए रहा।

- **हीरो मोटोकॉर्पोरेशन लिमिटेड**—17541 करोड़ जोड़े अपने मार्केट कैप में इस कंपनी की खास बात यह है कि एशिया अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका के 37 देशों में बिकती है कंपनी का बाइक्स एवं स्कूटर।
- **ल्यूपिन लिमिटेड**— 15693 करोड़ जोड़े अपने मार्केट कैप में। इस कंपनी की खास बात यह है कि ये कंपनी के भारत के अलावा अमेरिका जापान, ब्राजील और मैक्सिको में भी बड़े दवा मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट है।
- **वेदांता लिमिटेड**— 15631 करोड़ जोड़े अपने मार्केट कैप में। इस कंपनी की खास बात यह है कि कंपनी जल्द ही अपने शेयर का भारतीय शेयर बाजार से डिलिस्ट कराने वाली है नई विस्तार योजना पर काम जारी है।
- **पिरामल एंटर प्राइजेज**— 15357 करोड़ जोड़े अपने मार्केट कैप में। इस कंपनी की खास बात यह है कि इस कंपनी के चेयरमैन अजय पिरामल लायंस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुकेश अंबानी के समधी भी है।
- **बायोकोन लिमिटेड**— 14172 करोड़ जोड़े अपने मार्केट कैप में। इस कंपनी की खास बात यह है कि इस कंपनी की एक दवा को कोविड 19 में इमर्जेसी उपयोग की अनुमति मिली है और इस दवा का विदेशों में भी विस्तार है।
- **भारतीय इन्फ्राटेल**—13650 करोड़ जोड़े अपने मार्केट कैप में। इस कंपनी की खास बात यह है कि यह कंपनी भारतीय एयरटेल की सबसे बड़ी मोबाइल टॉवर कंपनियों में एक है। इस कंपनी का तेजी से कारोबार बढ़ रहा है।
- **हिंडालको इंडस्ट्रीज**— 11557 करोड़ जोड़े अपने मार्केट कैप में। इस कंपनी की खास बात यह है कि यह कंपनी आदित्य बिडला समूह की ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम रोलिंग करने वाली कंपनी है।
- **इन्फोएज इंडिया लिमिटेड**— 11328 करोड़ जोड़े अपने मार्केट कैप में। इस कंपनी की खास बात यह है कि यह कंपनी नौकरी डॉट काम जीवन साथी डॉट कॉक 99 एक डॉट काम आदि का संचालन करती है।
- **मदरसन सूमी सिस्टम** — 10720 करोड़ जोड़े अपने मार्केट कैप में। इस कंपनी की खास बात यह है कि यह कंपनी एशिया, यूरोप, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका आस्ट्रेलिया में इलेक्ट्रिक उपकरण सप्लाई करती है।
- **आयशर मोटर्स**— 10436 करोड़ जोड़े अपने मार्केट कैप में इस कंपनी की खास बात यह है कि इस कंपनी ने रायल इनफील्ड बाइक्स बुलेट को भारत के अलावा भी कई देशों में पापुलर बनाने में सफलता हासिल की है।

जिसमें प्रोफेशनल हो और वे भारतीय चुनौतियों के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चरणबद्ध तरीके से नीतिगत समाधान सरकार के सामने रखे। अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था आई एम एफ ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है इस टास्क फोर्स का

उद्देश्य है कि बिगड़ती हुयी अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाये इस टास्क फोर्स में आर.बी. आई. के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी है रघुराम राजन पहले भी आई एम एफ के साथ रह चुके हैं और वे एक काबिल अर्थ विशेषज्ञ है भारत को भी चाहिए कि अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भारत में भी प्रतिभाशाली अर्थशास्त्रीयों की एक कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें प्रोफेशनल हो और वे भारतीय चुनौतियों के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चरणबद्ध तरीके से नीतिगत समाधान सरकार के सामने रखे पिछले साल के ही आर्थिक सूचकांक को देखे तो आटोमोबाइल सेक्टर, रियल स्टेट, लघु उद्योग समेत तमाम असंगठित क्षेत्र में सुस्ती छाई हुई थी। बैंक एन पी ए की समस्या से अब तक निपट रही है हालांकि सरकार निवेश के जरिए, नियमों में राहत और आर्थिक मदद देकर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश कर रही थी पर बहुत अधिक सफलता सरकार को नहीं मिली है। इस बीच कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए हालात ने जैसे अर्थव्यवस्था का चक्का जाम कर दिया है न तो कही उत्पादन है और न मांगे, लोग घरों में हैं और कारखानों तथा दुकानों में ताले लगे हुए थे यह स्थिति 03 मई 2020 तक रही थी। कोरोना से लड़ाई अब दोहरी है। ज्यादातर देश सेहत और अर्थव्यवस्था दोनों का विनाश सीमित करने में जुटे हैं। भारत में संक्रमण रोकने के प्रयास जोर पकड़ रहे हैं लेकिन आर्थिक राहत में भारत पिछड़ गया है। इधर भारत में अब सबसे बड़ी चिंता इसलिए है कि भारत में अब कोरोना मरीज बढ़ते की रफ्तार

दुनिया में सबसे तेज है यू एस से दोगुनी भारत में इस महीने मरीज 3.6 प्रतिशत की दर से बढ़े, अमेरिका में 1.8 प्रतिशत की दर से यही रफ्तार रही तो 8 अगस्त तक देश में 22 लाख मरीज हो सकते हैं। भारत में नए कोरोना मरीज मिलने की रोजाना औसत दर 3.6 प्रतिशत हो गई है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। यानी भारत में अब नए मरीज सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने लगे हैं। सबसे ज्यादा 39 लाख मरीजों को अमेरिका में यह दर भारत से आधी 1.8 प्रतिशत बनी हुई है।

कोविड-19 संकट आने के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था नॉमिनल जी.डी.पी. के 11 साल के न्यूनतम स्तर पर भी बेरोजगारी की दर पिछले 45 साल में सबसे अधिक थी और ग्रामीण मांग पिछले 40 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर भी इसलिए बेहतर यह होगा कि जारी आर्थिक संकट को समझने के लिए पिछले दो वर्ष से चल रहे आर्थिक संकट को भी ध्यान में

लिया जाये तब जाकर कही कोविड-19 संकट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को दोबारा तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत नीति का निर्माण हो सकता है। वर्तमान की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक हरे संकट की तरफ बढ़ रही है। विभिन्न प्रतिष्ठित अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के संन्दर्भ में जो आँकड़े जारी किए हैं वे चिंताजनक हैं। वर्ल्ड बैंक ने दो संभावनाएँ जताई हैं पहली संभावना यह है कि अगर भारत सही वक्त पर सही तरीके से इसे कंट्रोल करने में कामयाब रहा तो अर्थव्यवस्था में जी.डी.पी. में वृद्धि दर 4 फीसदी रहेगी।

यदि रोजगार पर दृष्टि डाले तो लॉकडाउन की वजह से कुल 12 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। कोरोना संकट से पहले भारत में कुल रोजगार आबादी की संख्या 40.4 करोड़ थी जो इस संकट के बाद घटकर 28.5 करोड़ हो चुकी है।

## निष्कर्ष—

कोविड-19 के संकट का अभी सबसे बुरा दौर आना बाकी है यानी कि आज यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा दौर क्या होने वाला है हम अभी सिर्फ सम्भावनाएँ जता सकते हैं लेकिन यह जरूर स्पष्ट होता जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में मॉग एक पूर्ति के साथ-साथ बेरोजगारी का भीषण संकट आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्दों में कहे तो हमें जान और जहान दोनो को बचाना है लेकिन साथ ही अपने लोगों की जीविका को भी बचाने के लिए आर्थिक रूप से कुछ बड़े फैसले लेने होंगे।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची—

1. भारतीय अर्थव्यवस्था, डॉ० शर्मा एवं सिंह
2. भारतीय अर्थव्यवस्था, रुद्र एवं सुन्दरम एस.चॉन्द पब्लिकेशन दिल्ली
3. भारतीय अर्थव्यवस्था एस.एन अग्रवाल साहित्य भवन आगरा
4. भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्र एवं पूरी पब्लिकेशन मुम्बई
5. भारतीय राज्य व्यवस्था नरेन्द्र मदान, अष्टम प्रकाशन प्रथम संस्करण 1996
6. भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्र एवं पूरी हिमालय पब्लिकेशन दिल्ली
7. wikipedia.org
8. दैनिक समाचार पत्र एवं पत्रिका